दैनिक
पुष्पांजली टुडे
नई सोच नई पहल

वर्ष 03 : अंक : 305 | ग्वालियर, शुक्रवार 11 दिसम्बर 2020 | pushpanjalitoday@gmail.com | मूल्य : 01, रुपए, पृष्ठ 8

न्यूज ट्रैक

जेपी नड्डा पर हमलाः पश्चिम बंगाल में पहले भी हो चुके हैं राजनीतिक हमले, 2 साल में 6 हत्या

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी इस कदर बढ़ चुकी है हमले तक की नौबत आ गई है। सियासी रंजिश में कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले हुए। इतना ही नहीं बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थरों से हमले किए गए। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इस घटना की हर तरफ निंदा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमले की निंदा करते हुए कहा, तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दुखद भी है और चिंताजनक भी। पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी कई बार सियासी रंजिश में हमले हो चुके हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या भी की गई। बीते दो वर्ष में ही बड़ी घटनाओं पर नजर डालें तो आठ हमले हुए हैं और इनमें छह नेताओं और कार्यकर्ताओं की जान चली गई है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उपहार की गई जमीन पर कब्जा लेना उसे स्वीकारने जैसा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि उपहार की गई संपत्ति को लेने वाला यदि उसे लिखित में स्वीकार नहीं भी करता है, तो भी वह उपहार कानूनी रूप से योग्य माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह स्वीकारोक्ति उपहार लेने वाले के आचरण से तय की जाएगी, न कि लिखित सबूतों से। जस्टिस एन वी रमन्ना कि पीठ ने फैसले में राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय पलट दिया, जिसने उपहार को इस बिना पर खारिज कर दिया कि इसे लेने वाले ने इसे स्वीकार किया है, इसका कोई सबूत नहीं है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि उपहार स्वीकार कर लिया गया है, इसका अनुमान इस बात से लगता है कि उसने संपत्ति का कब्जा ले लिया है या स्वयं गिफ्ट डीड ही उसके कब्जे में है।संपत्ति स्थानांतरण एक्ट,1882 की धारा 122 के अनुसार गिफ्ट डीड के कानूनी होने की शर्तें यह है कि यह बिना किसी पैसे लिए की गई हो और पूरी तरह से स्वैच्छिक हो। इस तरह से संपति देने से दानकर्ता का पूरी तरह संपत्ति पर अपना मालिकाना हक छोड़ना है। उपहार लेने वाला देने वाले के जीवनकाल में इस संपत्ति को कभी भी स्वीकार कर सकता है। वहीं अचल संपत्ति स्थानांतरण के बारे में धारा 123 कहती है कि यह स्थानांतरण रजिस्टर्ड डीड पर होगा, जिसमें दानकर्ता के हस्ताक्षर हों और साथ में काम से काम दो गवाहों के भी हस्ताक्षर हों। कोर्ट ने कहा कि धारा 122 यह कहीं नहीं बताती कि उपहार कैसे स्वीकार कर लिया माना जाएगा, न ही स्वीकार करने का कोई विशेष तरीका परिभाषित करती है। कोर्ट ने कहा कि उपहार मंजूर करना इससे माना जा सकता है कि लेने वाले ने संपत्ति पर कब्जा ले लिया। या गिफ्ट डीड उसने दान करने वाले से अपने कब्जे में ले ली है। उपहार के प्रभावी होने की एक ही जरूरत है और वह यह कि इसे दान देने वाले के जीवनकाल में ही स्वीकार करना होगा।

क्या हरियाणा में टूटेगा बीजेपी-जेजेपी का गठबंधन ? सीएम और दुष्यंत चौटाला बोले...

चंडीगढ़। किसान आंदोलन को हरियाणा सरकार में बीजेपी के सहयोगी दल जेजेपी विधायकों द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद से यह अटकलें लगाई जा रही है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जल्द समर्थन वापस ले लेंगे। पर इसकी दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि राज्य में भाजपा-जेजेपी का गठबंधन मजबूत है और जेजेपी के कुछ विधायकों द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन का खुल कर समर्थन करने के बावजूद कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। वहीं सरकार से हटने के लिए विपक्ष और हरियाणा के कुछ किसानों की ओर से दबाव का सामना कर रहे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को खतरा होगा तो वह इस्तीफा दे देंगे।

क्या कहना है दुष्यंत चौटाला का

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उम्मीद जतायी कि किसान अब अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे क्योंकि सरकार ने एमएसपी और अन्य मांगों पर लिखित में आश्वासन दिया है। जेजेपी के नेता ने कहा कि उन्हें आशा है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान समझेंगे कि जब केंद्र ने लिखित में आश्वासन दिया है तो यह उनके संघर्ष की जीत है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि किसान केंद्र के साथ सुलह पर पहुंचेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, जब लिखित में आश्वासन दिया गया है तो मुझे नहीं लगता कि मुद्दे को आगे ले जाने की जरूरत है। चौटाला ने कहा कि वह किसानों के मुद्दे पर लगातार केंद्र के साथ संपर्क में थे और उनकी पार्टी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं । उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह गतिरोध खत्म होगा। राज्य में भाजपा

नेतृत्व वाली सरकार से हटने के लिए विपक्ष और हरियाणा के कुछ किसानों की ओर से दबाव का सामना कर रहे चौटाला ने कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को खतरा होगा तो वह इस्तीफा दे देंगे। उपमुख्यमंत्री ने अपने दादा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि सरकार किसानों की बात तब सुनती है जब सरकार में उनकी हिस्सेदारी होती है। हम और हमारी पार्टी किसानों की चिंताओं को सरकार के सामने रख रहे हैं। उनकी अपनी ही पार्टी के विधायकों द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन करने के बारे में पूछे जाने पर चौटाला ने कहा कि मैं सबसे पहले किसान हूं, क्या मैं इससे इनकार कर सकता हूं।

क्या कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का–मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि हमारा गठबंधन मजबूत है। कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। पिछले एक साल में हमने जो काम किया है, उससे अगले चार साल में विकास कार्यों में तेजी आएगी। राज्य मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक करने के बाद खट्टर से जेजेपी विधायकों द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के बारे में पूछा गया था, जिसपर उन्होंने यह कहा। जेजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक राम कुमार गौतम ने हाल ही में मांग की थी कि नये कृषि कानूनों को रद्द करने का केंद्र से अनुरोध करने के लिए एक प्रस्ताव लाने को लेकर राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। एक प्रश्न के उत्तर में खट्टर ने इशारा किया कि उनकी सरकार उन किसानों के साथ नरमी से पेश आएगी, जिन पर पिछले महीने हरियाणा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। यह पूछे जाने पर कि जेजेपी ने मामले वापस लेने की मांग की है, खट्टर ने कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अपने हैं, जो अपने होते हैं उनके साथ सारी चीजें ठीक होती हैं।

कोरोना का भयावह असर, नहीं लिया फोलोअप तो
40 फीसदी मरीजों का कैंसर तीसरे स्टेज तक फैला

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में कैंसर के ऐसे मरीज अब अस्पताल पहुंच रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में फोलोअप नहीं कराया था। दिल्ली स्थित एम्स, सफदरजंग और अपोलो जैसे अस्पतालों में कई ऐसे मरीज हाल ही में पहुंचे हैं जिन्हें पहले कैंसर पहली स्टेज में था लेकिन रेडिएशन थेरेपी के अभाव में और समय पर फोलोअप न कराने जी वजह से यह तीसरी स्टेज तक पहुंच गया है। कोरोना में कुछ लोगों ने डर की वजह से अस्पताल जाने में देरी की वहीं कुछ लोगों को समय पर इलाज ही नहीं मिल सका।

रेडियोथेरेपी न कराई तो सर्जरी के बावजूद अन्य अंगों तक फैल गया ब्रेस्ट कैंसर–पश्चिमी दिल्ली निवासी 33 वर्षीय स्नेहा की फरवरी में स्तन कैंसर की सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद उन्हें रेडिएशन थेरेपी की सलाह दी गई थी ताकि कैंसर दोबारा न उभरे। वे कोरोना के समय 6 महीने तक इसे टालती रहीं, अब पिछले महीने जब वे अस्पताल पहुंचीं तो उनका

स्तन का कैंसर न सिर्फ दोबारा उभर गया था बल्कि शरीर के दूसरे अंगों तक फैल गया था। अब उन्हें दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी और कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह हटाने में लंबा समय लगेगा।

सारकोमा कैंसर के फैलने की वजह से पैर काटना पड़ेगा–53 वर्षीय शकुंतला को जनवरी में सारकोमा कैंसर होने का पता चला। वह एम्स में इलाज करा रही थीं। लॉकडाउन की वजह से वह बिहार के मुजफ्फरपुर के गांव में लौट गईं। इस वजह से वह फोलोअप भी नहीं करा सकीं। जब वे 23 नवम्बर को एम्स में दिखाने के लिए गईं तो डॉक्टर ने जांच रिपोर्ट देखकर कहा कि कैंसर के जगहों तक फैल चुका है। यह पैर की कई हड्डियों तक पहुंच गया है। एम्स के सारकोमा विशेषज्ञ डॉक्टर समीर रस्तोगी ने बताया कि समय पर इलाज न मिलने की वजह से उनका कैंसर फैल गया। अगर वह समय पर फोलोअप कराती तो यह ठीक हो सकता है। संभव है महिला का पैर काटना पड़ जाए। डॉक्टर समीर ने कहा कि ऐसे कई मरीज अब तीसरी स्टेज के कैंसर के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं जिन्होनें समय पर फोलोअप नहीं कराया था।

40प्रतिशत मरीजों का कैंसर तीसरे स्टेज तक फैला–सरिता विहार स्थित अपोलो अस्पताल के डॉक्टर एस एम शोएब जैदी ने बताया कि उनके यहां आने वाले लगभग 40 फीसदी मरीजों ने समय पर फोलोअप नहीं कराया था।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव से पाक के आतंकी संगठनों में बौखलाहट, सुरक्षाबलों की मुस्तैदी से दहशतगर्दों के मंसूबे फेल

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के पांच चरणों मे पाकिस्तान की ओर से अस्थिरता फैलाने की पूरी कोशिश और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास के बावजूद सुरक्षा बलों ने नापाक मंसूबों को कामयाब नही होने दिया है। गुरुवार को पांचवे चरण के मतदान के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तान की शह पर काम कर रहे आतंकी संगठनों में बौखलाहट है। हिंसा को अंजाम देने की उनकी

कोशिश बुधवार को भी सुरक्षा बलों ने विफल कर दी थी। जब जैश के एक आतंकी को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार को भी छिटपुट प्रयास विफल कर दिए गए। सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि केंद्र व राज्य की एजेंसियो के साझा प्रयास से आतंकी संगठनों की सभी योजनाएं विफल साबित हुई हैं। समय पर मिल रही खुफिया सूचनाएं और उस पर समन्वित तरीके से त्वरित एक्शन से सुरक्षा बल आतंकियों पर भारी पड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि अभी भी आतंकी बड़ी वारदात की ताक में हैं, लेकिन इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं।

बिहार में आज सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर नहीं करेंगे मरीजों का इलाज

पटना। बिहार के सरकारी और निजी डॉक्टर शुक्रवार को अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा आयुर्वेद डाक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत देने संबंधी आदेश के खिलाफ इस आंदोलन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के साथ कई दूसरे संगठन भी शामिल होंगे। आईएमए के सचिव सुनील कुमार ने कहा है कि उनके संगठन की सभी शाखाओं के डॉक्टर सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक काम का बहिष्कार करेंगे। इस हड़ताल में कोविड और दूसरी जरूरी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। हड़ताल में आईएमए का सहयोगी संगठन जेडीएन और एमएसएन भी शामिल होगा। पीएमसीएच के आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर सचिदानंद कुमार और अमरकांत झा अमर करेंगे। एनएमसीएच में डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह और डॉक्टर अजय कुमार जिम्मेवारी संभालेंगे।

इसी तरह आइजीआइएमएस में डॉक्टर हरिहर दीक्षित जिम्मेवारी संभालेंगे।

एलोपैथिक डॉक्टरों की हड़ताल जनकल्याण विरोधी–आयुष मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मधुरेंदु पांडेय ने आयुर्वेद पीजी को सर्जरी की अनुमति दिए जाने के विरोध में एलोपैथिक चिकित्सकों की हड़ताल को जनकल्याण विरोधी बताया है। कहा है कि आइएमए ने अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा तो एलोपैथिक डॉक्टरों का व्यवसायिक बहिष्कार किया जाएगा।

ग्वालियर से प्रकाशित
दैनिक पुष्पांजली टुडे
राष्ट्रीय मासिक पत्रिका, ऑनलाइन न्यूज चैनल, पोर्टल, एंड्रॉयड ऐप
को
सम्पूर्ण भारत में नियुक्त करना है
ब्यूरो चीफ/रिपोर्टर
मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, गोआ, कर्नाटक, केरल
आदि राज्यों के जिला एवं तहसील स्तर पर मनोनीत करना है।
सम्पर्क करें
जी.एस. प्लाजा सूर्य मंदिर रोड गोले का मंदिर, ग्वालियर मध्यप्रदेश
मो. 7879637585, 8770253710
Website-www.pushpanjalitoday.com
Email.- pushpanjalitoday@gmail.com

केंद्रीय बलों के जवानों मिल रही है 100 दिनों की छुट्टी ?
गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से मांगा रिकॉर्ड

> केंद्रीय सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी शामिल हैं। यह निर्देश असम राइफल्स पर भी लागू होगा।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को निर्देश दिया है कि वे पिछले तीन साल में जवानों को दिए गए अवकाश की सूची बनाकर उनके मंत्रालय को भेजें। गृहमंत्री अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत जवानों को साल में कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ गुजारने का मौका देने के पक्ष में हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि गृहमंत्रालय ने सभी बलों को निर्देश दिया है कि वे अवर महानिदेशक (मानव संसाधन प्रभारी) रैंक के एक अधिकारी को इस काम पर लगाएं और अगले महीने के पहले सप्ताह तक इस संबंध में रिपोर्ट सौंपें। गृह मंत्रालय ने सभी बलों से पिछले तीन साल, 2018, 2019 और

2020 में जवानों को दी गई छुट्टियों का पूरा हिसाब मांगा है, ताकि पता किया जा सके कि गृहमंत्री का प्रस्ताव जमीनी स्तर पर लागू हो रहा है या नहीं। बलों से कहा गया है कि वे मंत्रालयों को अपने संख्या बल के बारे में बताएं, कितने लोगों को साल में 75 अवकाश पाने का अधिकार है और उनमें से कितने कर्मियों ने अपना अवकाश लिया है। कितने जवानों ने 60 से 74 अवकाश लिए हैं और उनमें से कितने सिर्फ 45 से 59 दिन अवकाश ले पाए हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी शामिल हैं। यह निर्देश असम राइफल्स पर भी लागू होगा। आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, शाह ने पिछले साल शुरू की गई इस योजना की हाल ही में समीक्षा करने के बाद यह निर्देश दिया है। इस योजना के तहत बलों को सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक जवान और अधिकारी साल में कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ गुजारें। इस योजना का लक्ष्य बेहद मुश्किल हालात में लंबी-लंबी शिफ्ट में काम करने वाले बलों में तनाव को कम करके खुशियों को बढ़ाना है।

सम्पादकीय

गलत बयानी

देश कोई भी हो, नेताओं में सजग नेतृत्व और उसके प्रति जिम्मेदारी का एहसास सबसे जरूरी है। लोकतांत्रिक देशों में तो यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि नेता जो भी बोलें, संभलकर बोलें। जब कोई दिग्गज नेता बोल रहा होता है, तब लोग दरअसल उसे इतिहास में दर्ज कर रहे होते हैं। मिसाल के लिए, ब्रिटेन की संसद में बुधवार को जब भारत में चल रहे किसान आंदोलन का मुद्दा उठा, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के जवाब ने सबको अचरज में डाल दिया। शायद उन्हें पता ही नहीं था कि लेबर पार्टी के ब्रिटिश सिख सांसद तनमनजीत सिंह धेसी ने क्या मुद्दा उठाया है। एक सामान्य नेता को भी संसद जैसी जगह पर हर पल सचेत रहना चाहिए, खासकर प्रधानमंत्री को तो और भी सावधानी से सबकी बात पर गौर करना चाहिए। ब्रिटिश सांसद ने भारत में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर सवाल पूछा, लेकिन जॉनसन ने जवाब दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी विवाद का हल द्विपक्षीय बातचीत से हो सकता है। जॉनसन से हुई यह गलती तत्काल चर्चा का विषय बनी और दुनिया ने देखा कि एक लोकतांत्रिक देश के चुने हुए नेता भी संसद में भी कितनी उदासीनता के साथ मौजूद रहते हैं। अव्वल तो इससे यह भी पता चलता है कि भारत के संबंध में ब्रिटिश नेताओं को कितनी कम जानकारी है। ब्रिटिश सांसद का सवाल तो खैर गलत था ही, ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी सचेत नहीं थे। उन्हें भारत जैसे लोकतांत्रिक और सेकुलर देश के बारे में बात करते हुए पूरी सावधानी से चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन किसान आंदोलन को सिर्फ सिखों का मामला समझ लेना और ब्रिटिश सिखों की ओर से चिंता या सवाल का इजहार करना कतई प्रशंसनीय नहीं है। भारत में किसान आंदोलन को केवल सिखों का आंदोलन कैसे माना जा सकता है? सिर्फ सिखों के प्रति चिंता का इजहार कैसी राजनीति है? यह हमारे लिए चिंता का समय है, जब दुनिया में अनेक नेता किसी मामले को पूरा जाने बगैर बयान देने की जल्दबाजी दिखाने लगे हैं। ऐसी ही जल्दबाजी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेव ने भी दिखाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो अपने बयानों के लिए खासे चर्चित रहे हैं। जो भी मन में आए, बोल देने और कथनी-करनी में भेद रखकर चलने की रियायत किसी भी तंत्र के लिए खतरनाक है। पूरी जानकारी न रखने वाले नेताओं में भी बढ़ता बड़बोलापन शर्मनाक है। आए दिन ऐसे बयान आते हैं कि बयानबाज नेता की सामान्य बुद्धि पर भी संदेह होता है। पहले माना जाता था कि विपक्ष के नेता आलोचना में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अब सत्ता पक्ष की ओर से भी तथ्य-तर्क से परे बयानबाजी आम हो गई है। सत्ता पक्ष का ही एक हिस्सा नरमी की बात करता है, तो दूसरा आग में घी डालने में कसर नहीं छोड़ता। नेता ऐसा करते हुए राजनीति और जनमानस, दोनों को भटकाते हैं। एक ओर, कहा जाता है, किसान देश में कहीं भी अनाज बेच सकता है, तो दूसरी ओर से यह बयान आता है कि दूसरे राज्यों के किसान आए, तो खैर नहीं। राजनीति में ऐसी उदासीनता, लापरवाही, जमीनी अध्ययन और तैयारी की कमी देश या समाज ही नहीं, स्वयं राजनीतिक बिरादरी की सेहत के लिए नुकसानदायक है। लोग यही चाहेंगे कि उनके नेतृत्वकर्ता पर्याप्त जानकारी के बाद ही किसी मुद्दे पर मुंह खोलें।

कुछ पल सुखद होतें है

कुछ पलों ने मन को दी पीड़ा,
कुछ पल थे सादे सादे,
कुछ पलों में थी रोशनाई,
कुछ पलों ने बगिया अपनाई,
कुछ भवरों ने कलियों को छेड़ा,
कुछ कलियां भी बहुत शरमाई,
कुछ पुष्प साथ छोड़ गए,
कुछ फूलों ने गगन को चूमा,
कुछ फूल धरा पर लेट गए,
कुछ पल कानों में मधु रस घोल गए,
कुछ पल वियोग का रस छोड़ गए,
चलो भूले कल की तरुणाई को,
आया तेजस्वी युवा सवेरा है,
सूरज की रोशनी में,
ऊर्जा शक्ति का बसेरा है,
स्वीकारे,
नव पल की स्फूर्त किरणों को,
नव संकल्प, नव उद्देश,नव आशाओं का,
स्वागत करें ईश्वर के आशीर्वचनो का,
नवीन मीठे आस्था से ओत प्रोत पलो के संग संग,
समस्त मंगल कामनाएओं के साथ ,
सादर,

संजीव ठाकुर, अन्तराष्ट्रीय कवि, रायपुर, छत्तीसगढ़

भक्ति...

भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है,
भोजन प्रसाद बन जाता है ।
भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है,
भूख व्रत बन जाती है ।
भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है ,
पानी चरणामृत बन जाता है ।
भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है ,
सफर तीर्थयात्रा बन जाता है ।
भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है ,
संगीत कीर्तन बन जाता है ।
भक्ति जब घर में प्रवेश करती है ,
घर मन्दिर बन जाता है ।
भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है ,
कार्य कर्म बन जाता है ।
भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है ,
क्रिया सेवा बन जाती है ।
भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है ,
व्यक्ति मानव बन जाता है..।

स्वरचित एवं मौलिक
मनोज शाह मानस
सुदर्शन पार्क, मोती नगर

बाल कविता

बचपन

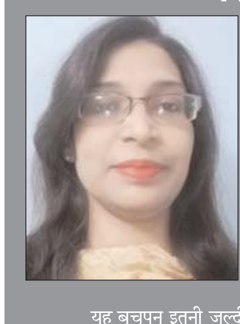

छोटा मन छोटी आशा कहां समझे
बड़ों की भाषा
बचपन सबसे सुंदर होती निश्चल
मन मदमस्त है रहती।।
अमीर गरीब का पाठ न जाने बस
प्रेम सदभाव है जाने
रंग बिरंगे फूलों संग ये बहते यहां
वहां कहीं ना ठहरते।।
मनमोहक मुस्कान से मन मोह लेते
हैं पंख लगा कर क्यों
यह बचपन इतनी जल्दी दूर कहीं उड़ जाते हैं।।
फूल फूल कली कली मुस्काता यह अल्हड़ बचपन
कहां मिलती ऐसी आजादी चाहे उम्र हो जाए पचपन।।

निक्की शर्मा रश्मि, मुम्बई

एडमिन की परिभाषा कड़वी है पर सच्ची है

एडमिन यानी व्यवस्थापक, एक अच्छा व्यवस्थापक अपने समूह का पसंदीदा व्यक्तित्व होता है एक आदर्श होता है। आजकल फेसबुक, वोटसएप पर ग्रुप बनाकर चलाने वाले एडमिन खुद को कोई राजा महाराजा या महारानी समझने लगते है। इतनी अकड़ तो किसी कोर्पोरेट जगत में मैनेजर की पोस्ट पर बैठा इंसान भी नहीं दिखाता, नांहि प्रधानमंत्री। एडमिन ये भूल जाते है की ऑफ़िस हो या ग्रुप उनकी ये दुकान कर्मचारी और मेम्बर्स से चलती है। एक अच्छा एडमिन वो है जो सबको साथ लेकर चलता है। मेम्बर्स को एडमिन की जरूरत नहीं होती बल्कि ग्रुप को सुचारु रुप से चलाने के लिए एडमिन को अच्छे मेम्बर्स की जरूरत होती है। कोई-कोई एडमिन तो इतनी तीखी, बेरुख़ी भरी धमकी की भाषा में मेम्बर्स के साथ बर्ताव करते है मानों मेम्बर्स कोई तुच्छ प्राणी हो या प्यून हो। कौन टिकेगा वहाँ ? ज़ाहिर सी बात है इंसान को जहाँ प्यार, अपनापन और सम्मान मिलेगा उस जगह को छोड़ कर कभी नहीं जाएगा। और जहाँ सदस्यों में भेदभाव रहेगा और एडमिन शिक्षक सा बर्ताव करेगा वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता सारे कट लेंगे। तू नहीं और सही ग्रुपों की कमी नहीं। अगर मेम्बर्स से गलती होती है तो समझाने के दो तरीके होते है प्यार और इज्जत से भी समझाया जाता है। पहले चेतावनी दो समझा बूझाकर फिर धमकी दो। और भाषा में मिठास होनी चाहिए की आप अपनी बात बोल भी दो और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। दूसरी बात कई साहित्यिक ग्रुपों में मेम्बर्स को रचनाएँ छपवाने के बदले सदस्यता फीस के नाम पर पैसे वसूले जाते है। या तो हर महीने कोई ना कोई विषय देकर साझा संग्रह के नाम पर सिर्फ़ दो या तीन पेज के 700 से लेकर 1500 रुपये तक की मांग करते है। पहली बात तो ये की मेहनत लेखक करे, दिमाग लेखक खपाए और उस बात के पैसे भी दे। अगर अपनी रचनाएँ छपवानी होगी तो खुद की एकल अपनी मर्ज़ी से छपवाएंगे। और कई जगह पर जो लोग 500/1000 देकर साझा संकलन में साझेदारी करते है उनकी फालतू जैसी रचनाएँ भी उस ग्रुप की पत्रिका में छाप देते है, और अच्छे-अच्छे रचनाकारों की रचनाएं पड़ी रहती है। एक लेखक रचना छपवाने के लिए कितने पैसें देता रहेगा, और कितनी साझा किताबें जमा करता रहेगा। कुल मिलाकर साहित्यिक जगत आज पब्लिशर्स के लिए व्यापार बन गया है। किसीको अच्छी रचनाओं और अच्छे लेखन से नहीं जो पैसे दे उसकी रचनाओं से मतलब होता है। माना कोई किसीके लिए मुफ़्त में कुछ नहीं करता सबको अपना घर चलाना होता है पर साहित्य का खून करके सिर्फ़ पैसों की ख़ातिर कुछ अच्छे लेखकों के साथ नाइन्साफ़ी जायज़ नहीं। हर कोई अच्छा लिखने वाला इतनी फीस देने के लिए सक्षम नहीं होता। पहले के ज़माने में लेखक को मानदेय राशि मिलती थी आज देनी पड़ रही है। ऐसे ग्रुपों में भी कोई-कोई एडमिन तो ग्रुप पर खुद का आधिपत्य समझते है और किसीको टिकने ही नहीं देते। जैसे खुद कोई नेता हो और दूसरा आकर मानों उसकी कुर्सी छीन लेगा। अरे भै महज़ ग्रुप है इतनी खिंचातानी क्यूँ ? एक की जगह दो और दो की जगह तीन मिलकर काम करोगे तो और अच्छे से चलेगा। कोई कोई एडमिन अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत लेता है तो कुछ इंसान की फ़ितरत कभी नहीं बदलती। ना होंठों पर हंसी होती है ना जुबाँ पर सरस्वती और खुद को लाट साहब समझते एडमिन तो बन बैठते है पर किसीका आदर्श नहीं बन पाते।

(भावना ठाकर,बेंगुलूरु) प्तभावु

आभार अर्धांगिनी

हम बस प्रिय -प्रिये नहीं,
हम कदम-कदम के साथी हैं।
हम बस दो जिस्म नहीं,
हम जन्मों-जन्म के साथी है।।
तुम ही हो मेरी सब खुशियाँ,
तुम्हारी बाहों में है मेरी दुनियां।
सिर रख गोद में तेरे मैं सोऊ,
संग तेरे दिखे खुशियों की बगियां।।
तेरे उलझे केशों को सुलझाऊ,
तेरे नयनों में खुद समा जाऊं।
जीवन में दो रोटी कमा लाऊ,
पहली मैं तुझे खिलाऊं,
दूसरी फिर मैं खुद खाऊ।।
पैसों से है हम निर्धन प्रिये,
तिजोरी में रखते तस्वीर तेरी।
ऊंचे महलों के हम नहीं वासी,
तेरे नयन है, मेरे सुखद आवासीय।।
दिलों में है बस प्यार तुम्हारा,
तुम हो मेरे जीवन का सहारा।
इक चाहत है इस जीवन में,
पग-पग पर हो साथ तुम्हारा।।
ऑफिस से जब थका आता हूं,
देख तुम्हे मैं मुस्कराता हूं।।

तुम्हारे हाथों से बने चायों से,
खुद को मैं तरोताजा पाता हूं।।
बच्चा मेरा रातों में तंग करता,
मैं अपनी निद्रा में मस्त रहता।।
खुद जगकर तुम उसे सुलाती,
सुबह फिर मधुर मुस्कान बिखेरती।।
हर पल तुम रहोगी मेरा सहारा,
सातों जन्मों तक होगा साथ हमारा।
हर एक परिस्थिति में तुम साथ रहना,
बुढ़ापे की तू मेरी बुढ़िया, मैं बुड्ढा तुम्हारा।।
छोड़कर अपना घर, साथ मेरे ब्याह तुम आई,
सुख-दुख दोनों में, साथ तुम मेरे बिताई।
कैसे करू मैं प्रिये आभार तुम्हारा ?
जो जीवन के हर रश्म तुमने निभाई।।
ना जाने कितने बसंतो का हूं ऋणी तुम्हारा,
इस जीवन को बस है अब तुम्हारा सहारा।।
छोड़ ना अर्ध-मार्ग में तुम हमको जाना,
तुम्हारे बाद कोई ना है दूजा हमारा।।

अंकुर सिंह
चंदवक जौनपुर
उत्तर प्रदेश -222129

क्या किसान के संकटमय जीवन का कोई स्थायी समाधान है?

भारत में खाद्य संकट इतिहास का हिस्सा बन गया है। लेकिन 60 के दशक के पहले ऐसा नहीं था। पिछले 14 दिनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे पंजाब-हरियाणा के किसानों का कहना है कि भारत को खाद्य संकट से बाहर निकालने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। इस बात में सच्चाई भी है। अब जब भारत खाद्य संकट से बाहर निकल गया है और गेहूं-चावल का उत्पादन इतना हो रहा है कि रखने की जगह नहीं है तब सरकार को लगता है कि एमएसपी उसके लिए बोझ है और इसका कोई उपाय होना चाहिए। मोदी सरकार ने जो नए तीन क़ानून बनाए हैं उनमें कृषि उपज की मंडी, ख़रीदारी और उत्पादन को नियंत्रण मुक्त करने पर ज़ोर है। किसान अपनी फसल, खेत से राज्यों की अनाज मंडियों में पहुँचाते हैं। इन फसलों में गेंहू और चावल को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया एमएसपी दर से ख़रीदती है। एफसीआई किसानों से ख़रीदे इन अनाजों को ग़रीबों के बीच सस्ती दर पर देती है। लेकिन एफसीआई के पास अनाज का स्टॉक इसके बाद भी बचा ही रहता है। ग़रीबों के बीच अनाज पीडीएस के तहत दिया जाता है। पीडीएस, भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, जो दुनिया की सबसे मंहगी खाद्य सुरक्षा प्रणाली में से एक बताई जाती है। इस योजना के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर ग़रीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और ग़ैर-खाद्य वस्तुओं को वितरित करती हैं। यानी एसएसपी वाली फसलों की क़ीमतें सरकार तय कर देती है, तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि किसानों को अपनी फसल की एक निश्चित क़ीमत मिल जाएगी। नए कृषि क़ानून के आने के बाद से किसानों को लग रहा है कि अब प्राइवेट प्लेयर बाज़ार में आ जाएँगे और मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में उनकी एमएसपी की सुनिश्चित आय ख़त्म हो जाएगी। यहाँ ग़ौर करने वाली बात ये है कि एमएसपी चाहे 23 फसलों के लिए हर साल घोषित हो, सरकार गेंहू, चावल के अलावा कपास जैसी एक दो और फसलें ही हैं जो मंडी में जाकर एमएसपी दर से किसानों से ख़रीदती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फसलों की क़ीमतें बाज़ार के हिसाब से ही तय होनी चाहिए ना कि सरकार द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए। किसानों को और भारत सरकार को चाहिए की खेती में लगने वाली लागत को कम करें। एमएसपी से ही किसानों का भला हो सकता है, ये अवधारणा ग़लत है। दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि जो व्यवस्था 94 फ़ीसदी के लिए लाभकारी नहीं है, वो भला देश के किसानों को स्थायी संकट से उबारने का ज़रिया कैसे हो सकती है।

अंतरराष्ट्रीय सूत्रों की मानें तो सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है और फसलों की ख़रीद पर एमएसपी भी देती है, जो अंतरराष्ट्रीय बाज़ार भाव से ज़्यादा होती है। ऐसा दुनिया के किसी दूसरी अर्थव्यवस्था में नहीं होता। इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भारत के गेंहू को आस्ट्रेलिया और यूक्रेन के गेंहू से कड़ी टक्कर मिल रही है और भारत के गेंहू की क़ीमतें काफ़ी ज्यादा हैं। इस वजह से निर्यात पर काफ़ी असर पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त एक और दिक्क़त है। एफसीआई के नियमों के मुताबिक़, कुल ख़रीद का 8 फ़ीसदी तक ख़राब पैदावार आप ख़रीद सकते हैं। यानी 8 फ़ीसदी गेंहू जो सरकार ख़रीदती है उसके पैसे भी देती है पर वो इस्तेमाल के लायक नहीं होता। इससे आप आंकलन कर सकते हैं कि एमएसपी से भले ही किसानों को फ़ायदा पहुँच रहा हो लेकिन इससे भारत के खेती किसानी का संकट टल नहीं रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्यवस्था से 94 फ़ीसदी किसान बाहर हैं। जिस तरह से किसान अपनी बात मनवाने के लिए एकजुट और संगठित हैं, मान लीजिए केंद्र सरकार क़ानून बना देती है कि एमएसपी से नीचे फसलों की ख़रीद अपराध होगा। लेकिन किसी भी प्राइवेट प्लेयर को सरकार फसल ख़रीदने पर मजबूर नहीं कर सकती। क़ानून प्रस्तावित होने के बाद अगर व्यापारी एक जुट हो कर कहें कि वो एमएसपी पर फसल नहीं ख़रीद सकते, तो सरकार क्या करेगी? ऐसे में सरकार पर इन फसलों की ख़रीद का दबाव बढ़ेगा। अब चूँकि ये क़ानून है तो सरकार को ये 23 फसलों की ख़रीद करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किसानों को एमएसपी देने के बाद भारत विश्व व्यापार संगठन में जाकर बेहतर तरीके से मोल-भाव नहीं कर पाते हैं। अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक़, कोई देश कृषि जीडीपी के 10 फ़ीसदी तक ही किसानों को सब्सिडी दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में एमएसपी भी सब्सिडी का ही एक तरीक़ा माना जाता है। हर जगह पीडीएस में गेंहू, चावल देने की ज़रूरत नहीं है। हर राज्य में जो वहाँ का मुख्य भोजन हो जिसकी पैदावार वहाँ होती है वहीं देने की व्यवस्था लागू करके सरकार को फसल की उत्पादकता बढ़ाने, फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने और किसानों की फसलों की क़ीमत तय करने की ताक़त बढ़ानी चाहिए। 60 के दशक में जब एमएसपी लाया गया था, तब भारत खाद्यान में आत्मनिर्भर नहीं था। लेकिन आज भारत के पास गेंहू और चावल दोनों ज़रूरत से ज्यादा मात्रा में गोदाम में पड़े हैं। अधिक क़ीमत और कहीं-कहीं ख़राब क्वालिटी की वजह से इनका निर्यात नहीं हो पा रहा है।

प्रफुल्ल सिंह बेचैन कलम
युवा लेखक एवं साहित्यकार

यौन हिंसा

यौन हिंसा एक वैश्विक मुद्दा है और कई रूप में जन्म लेता है। 2013 में बस की सवारी करते समय एक भारतीय युवती के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार और 2015 में खोई हुई नाइजीरियाई लड़कियों को आतंकवादी समूह बोको हरम द्वारा अपहरण कर दुनिया के सामने यौन उत्पीड़न की भयावह तस्वीर प्रस्तुत की है। कैंपस यौन हमला इस मुद्दे का एक और पहलू है जिसने सहमति, बलात्कार, और महिलाओं के लिए शैक्षिक इक्विटी की खोज पर एक राष्ट्रीय वार्तालाप को बढ़ावा दिया है। हम एक कैंपस कल्चर कैसे बनाते हैं जो वर्तमान आंकड़ों को बदल देता है - 5 में से 1 महिला अपने कॉलेज के करियर के दौरान यौन उत्पीड़न करती है? यौन हिंसा का खुलकर समर्थन करने वाली राष्ट्रीय संस्कृति महिलाओं, ट्रांस-महिलाओं और लड़कियों के आत्म-सम्मान और उनकी दृष्टि को प्रभावित करती है जो वे दुनिया में हो सकती हैं? महिलाएं अभी भी दुनिया की सबसे गरीब नागरिक बनी हुई हैं और अक्सर श्रम और यौन तस्करी के विभिन्न रूपों का शिकार होती हैं। वैश्वीकरण, सैन्य संघर्ष, प्रवासन और गरीबी के नारीकरण के प्रभावों ने इन स्थितियों में कैसे योगदान दिया है? मानव कामुकता का अध्ययन अपने कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक विन्यास में शक्ति के बारे में गंभीर रूप से सोच के साथ प्रतिच्छेद करता है। कामुकता का अध्ययन सामाजिक भिन्नता की परीक्षा और जाति, लिंग, वर्ग, विकलांगता, धर्म, राष्ट्रीयता और जातीयता के साथ इसके परस्पर संबंध के लिए एक महत्वपूर्ण लेंस प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र का एक प्रभाग, स्वास्थ्य को मोटे तौर पर 卐पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति की स्थिति卐 के रूप में परिभाषित करता है। चिकित्सा प्रदाताओं द्वारा गरिमा के साथ व्यवहार करने और अपने शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए महिलाओं के संघर्ष ने पिछले 50 वर्षों में समकालीन सक्रियता को परिभाषित किया है। विश्व स्तर पर, महिलाओं ने उन तरीकों को प्रलेखित किया है जिसमें नियोक्ता, चिकित्सा संस्थान और सरकारें अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की अनदेखी करते हैं और गर्भनिरोध, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों, व्यापक प्रजनन स्वास्थ्य तक पहुँच के लिए अपनी ओर से संगठित होते हैं - जिनमें सुरक्षित गर्भपात तक पहुँच शामिल है - और चिकित्सा अनुसंधान में शामिल करना। उन्होंने सांस्कृतिक मान्यताओं की भी पहचान की और उन्हें चुनौती दी, जो महिलाओं के शरीर को पुरुषों के शरीर से हीन मानती हैं। ऐतिहासिक रूप से और यहां तक कि आज भी, दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को कानून और नीतियों के निर्माण में एक सार्थक भूमिका निभाने से बाहर रखा गया है। महिलाओं को अक्सर कानूनों और नीतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके जीवन के अनुभवों को अनदेखा करते हैं या सक्रिय रूप से उनके हितों के खिलाफ काम करते हैं। सभी पृष्ठभूमि की महिलाएं (जैसे, विषमलैंगिक, समलैंगिक, किन्नर, ट्रांसजेंडर) अपने पूरे जीवन में लिंग आधारित हिंसा का सिलसिला अनुभव करती हैं। लिंग आधारित हिंसा कई रूप ले सकती है, जिनमें शामिल हैं- लेकिन केवल यौन उत्पीड़न, बलात्कार, कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न, पीछा करना, घरेलू या पारस्परिक हिंसा और सड़क उत्पीड़न तक सीमित नहीं है। लिंग आधारित हिंसा महिलाओं के नागरिक और निजी जीवन दोनों के अनुभव को गंभीर रूप से कम कर सकती है, यहां तक कि महिलाओं को सीमाओं के पार और उनके घरों, समुदायों और देशों से दूर ले जाती है। उपनिवेशवाद, गरीबी, वर्गवाद, नस्लवाद और पितृसत्ता की विरासत सभी लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने में एक भूमिका निभाते हैं। लिंग आधारित हिंसा, राजनीतिक निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं की कमी, प्रतिबंधित प्रजनन अधिकार और असमानता के लगातार रूप प्रमुख तंत्र हैं जो स्थानीय और विश्व स्तर पर महिलाओं के सुरक्षा के अनुभवों को आकार देते हैं। महिलाएं और बच्चे सांप्रदायिक संघर्ष और युद्ध से नाटकीय रूप से प्रभावित होते हैं। यह महिलाओं और लड़कियों के शैक्षिक और श्रम के अवसरों, स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित कर सकता है और यौन हिंसा के जोखिम को बढ़ा सकता है। विश्व स्तर पर, महिलाओं का काम अक्सर असुरक्षित, अस्वास्थ्यकर, क्षणभंगुर और अंडरपेड होता है। श्रमिकों के रूप में महिलाओं को अक्सर यौन उत्पीड़न, उचित और समान वेतन की कमी और विषाक्त स्वास्थ्य वातावरण के साथ संघर्ष करना पड़ता है। देश की यौन उत्पीड़न की संस्कृति पर से पर्दा उठाते हुए ऊंचाइयों तक ले जाया जा रहा है। प्तमी टू आंदोलन द्वारा सशक्त, महिलाएं और उनके सहयोगी टीम बना रहे हैं और पहले की तरह बोल रहे हैं। गायकी की इस लहर के साथ लोक चेतना में परिवर्तन आता है। समाज के हर क्षेत्र की विविध महिलाओं की आवाज़ और अनुभव सही सुनाई देने लगे हैं - और यौन दुराचार के अपराधियों को आखिरकार जवाबदेह ठहराया जाता है। पितृसत्ता और श्वेत वर्चस्व के लिए सबसे शक्तिशाली मारक एक मजबूत नारीवादी शिक्षा और सामाजिक न्याय आंदोलनों में व्यापक भागीदारी है जो हमारे कानूनों, संस्थानों और रीति-रिवाजों में बदलाव की मांग करती है।

सलिल सरोज
नई दिल्ली

मानवाधिकार दिवस पर हमें मास्कमैन बने, बिहार के लेखक की तारीफ करनी चाहिए, जिन्होंने कोरोनाकाल में मुफ्त में बावन हज़ार (52,000) से ऊपर मास्क वितरित किये।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर और इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर के साथ दर्जनों भर से अधिक रिकार्ड्स बुक में अपने नाम को दर्ज कराने वाले वेंटिलेटर इश्क़ के लेखक मनु ने मानवता की एक नई मिसाल पेश किए हैं; उन्होंने कोरोनाक़ाल में 52,000 से ऊपर लोगों को मुफ्त मास्क वितरित किए। वैसे कुछ माह तक वे सपरिवार सिलाई कर मास्क बनाते थे और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाते थे; लेकिन अत्यधिक लोगों के पास मास्क पहुँचे, इस सोच के कारण उपन्यास से प्राप्त रॉयल्टी राशि का उपयोग वह करने लगे ! हमें मालूम होनी चाहिये कि बेस्टसेलर उपन्यास वेंटिलेटर इश्क़ से प्राप्त रॉयल्टी राशि का अधिकतर भाग लेखक हर माह वीर शहीद परिवारों के पास भी भेजते रहे हैं, इतने अच्छे सामाजिक कार्य करने के कारण लोगों ने उनका नाम मास्कमैन रख दिये हैं ! ऐसे महान इंसान को आदर सहित प्रणाम।

अद्वैता कुमारी,
शहर - कानपुर,
शिक्षा - इंटरमीडिएट

सबक सहानुभूति से

आज सबक मिला है मुझे
नई नई चीजों का
सबक मिला है मुझे
जब मेरा एक्सीडेंट हुआ
जब मैं मेरे जख्मों से अनजान थी
मुझे नहीं दर्द की कोई पहचान थी
जब अपनों ने सहानुभूति दिखाई
तब मुझे थोड़ा दर्द समझ में आई
सहानुभूति क्या है??
यह बात आज मुझे समझ में आई
सहानुभूति! यह भी
दर्द को बढ़ाने की दवा है
जब साथ ना मिले सहानुभूति का
इंसान अपने आप में बड़ा हैं
और उसका जख्म भी छोटा है
जब मिल जाए सहानुभूति का साथ
छोटी मोटी चोट में भी
निकल जाती है मुंह से आह
आज सबक मिला है मुझे
आज सबक मिला है मुझे

बबली कुमारी
डेहरी ऑन सोन रोहतास (बिहार)

हैदराबादी सियासत के निहितार्थ

तेलुगु मतदाताओं ने एक ट्रेंड स्थापित की है। वे बदलाव को शिद्दत से स्वीकार करते हैं और नए सियासी गठबंधन को सिर-माथे पर बिठाते हैं, लेकिन जब वे उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो उनको सत्ता से बाहर करने में भी देरी नहीं करते। पिछले हफ्ते आए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों के नतीजे इसी प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। इनमें भाजपा ने चुनाव-पूर्व अनुमानों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि महज छह साल पहले बड़े उत्साह के साथ के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को गले लगाने वाले मतदाता अपना रवैया न सुधारने की वजह से उसे जमीन दिखाने को तैयार हो गए हैं। हालांकि, इस बार जो बात अलग है, वह है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चरम दक्षिणपंथी तरीकों के इस्तेमाल की भाजपाई रणनीति। उसने ऐसा अपनी जगह बनाने के लिए किया। जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक अब अतिरेकी दावा करने लगे हैं। वे कहने लगे हैं कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव का यह नतीजा अगले साल हो रहे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों पर खासा असरंदाज होगा। बेशक यह परिपक्व बयानबाजी नहीं कही जाएगी, लेकिन सच यह भी है कि भगवा पार्टी को दक्षिण में अच्छी कामयाबी मिली है और वह इस माहौल का इस्तेमाल पूरब के चुनावी अभियानों में करेगी। अगर हम इतिहास में झांकें, तो 1980 के दशक की शुरुआत में, अविभाजित आंध्र प्रदेश में अभिनेता से नेता बनने वाले एन टी रामाराव ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। तब तेलुगु अस्मिता के नाम पर उन्हें यह सफलता मिली थी। उनका चुनाव अभियान दरअसल, उस घटना के विरोध में शुरू हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री टी अंजैया को राजीव गांधी (जिन्हें इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था) ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था।

किसान

खेतों में फसलें लहराते।
अन्न किसान उगाते हैं।।
कड़ी धूप में दिनभर रहते ।
तब वह भोजन खाते हैं।।
बंजर धरती सोना उगले।
कड़ी मेहनत करते हैं।।
गर्मी ठंडी बरसातों में।
नही किसी से डरते हैं।।
फसल जीवन भर वे उगाते।
तभी बैठ के खाते हैं।।
बूँद पसीना रोज बहाते।
तब वह घर पर आते हैं।।
अब क्या होगा सोंच रहे हैं।
अन्न कहाँ से लायेंगे।।
घर में भूखे बच्चें सोते।
भोजन कैसे खायेंगे।।
कुछ तो दया दिखाओ भगवन।
बच्चें भी अब रोते हैं।।
अन्न नही है खाने को अब।
भूखे रहकर सोते हैं।।

रचनाकार
प्रिया देवांगन प्रिय÷
पंडरिया

सुमित छारी को सौंपी गई भारतीय नमो संघ जिला उपाध्यक्ष की कमान

मोदी जी की नीतियों विचारों एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना ही नमो संघ का उद्देश

भिंड । भारतीय नमो संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार मन्नू जी और नमो संघ संरक्षिका भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री पूजा कपिल मिश्रा जी के निर्देश पर नमो संघ के चल रहे संगठन विस्तार के तहत भारतीय नमो संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेता मुकेश दीक्षित की अनुशंसा पर भिंड जिला शहर अध्यक्ष हिरदेश सोनी और भिंड जिला अध्यक्ष ब्रजेश तिवारी के द्वारा भिंड जिला उपाध्यक्ष पद पर सुमित छारी को मनोनीत किया गया, इस अवसर पर नवनियुक्त भारतीय नमो संघ भिंड जिला उपाध्यक्ष सुमित छारी ने कहा कि संगठन ने मुझे जो दायित्व सौंपा है उसे मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करूंगा,और मोदी जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा, इसके बाद नमो संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश दीक्षित ने कहा के भारतीय नरेंद्र मोदी संगठन स्वच्छ राजनीति से प्रेरित एक सामाजिक संगठन है और हमारा उद्देश्य राष्ट्र हित में काम कर रही भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना एवं मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार कर आम लोगों को उनका फायदा दिलाना है नमो संघ का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत

जातिवाद अलगाववाद मुक्त अखंड भारत का निर्माण करना है इस संगठन का निर्माण 10 वर्ष पूर्व मोदी एक विचार को लेकर किया गया था इस संगठन का निर्माण आरएसएस और भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा किया गया है आज नमो संघ पूरे भारत में राष्ट्र सेवा में समर्पित होकर कार्य कर रहा है उन्होंने आगे कहा जो देश में पिछले 70 वर्षों में नहीं हो पाया वह मोदी जी ने करके दिखा दिया है आज पूरे विश्व में नमो की गूंज है और आज हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में अखंड भारत निर्माण की ओर अग्रसर है अब वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश विश्व गुरु कहलायेगा, इस अवसर पर नवनियुक्त भिंड जिला उपाध्यक्ष सुमित छारी ने कहा कि भारतीय नमो संघ का एक-एक कार्यकर्ता , जनकल्याण अनाथ और असहाय बेबस गरीब सर्वहारा वर्ग कल्याण के लिए कार्य करने हेतु संकल्प बद्ध है, इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी नमो संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष सुमित छारी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, और उन्हें बधाई दी, जिले ओर प्रदेश के कई भाजपा ओर नमो संघ के पदाधकारियों कार्यकर्ताओं ने बधाई दी।

गोहद अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत सह संगठन मंत्री एवं पुष्पांजलि टुडे के ग्वालियर संभाग रिपोर्टर महेंद्र शर्मा जी का कल दिनांक 9 दिसंबर 2020 को दोपहर 3:00 बजे ग्वालियर से भिंड रोड पर टोल प्लाजा के पास एक्सीडेंट को हुआ है। वह संगठन के कार्य हेतु अपने गांव बिरखड़ी गोहद से अपनी बाइक से ग्वालियर होते हुए मुरैना जा रहे थे। ग्वालियर आदित्यपुरम में उनके परिवार में शादी भी थी । इसलिए उनकी पत्नी भी साथ में थी दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं वो केवल पच्चीस तीस की रफ्तार में चल रहे थे पीछे से इको मारुति कार के ड्राइवर ने तेज लापरवाही से चलाते हुए जबरदस्त टक्कर मारी और वे बुरी तरह जख्मी हो गए उनके शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। वही उनकी पत्नी के दोनों पैरों में बहुत गंभीर चोटें आई हैं ।एक पैर की तो नस कटने से काफी मात्रा में ब्लड निकल रहा था। मुरार हॉस्पिटल में डॉक्टर कुशवाह ने गंभीर हालत देखते हुए जयारोग्य रेफर किया लेकिन उनके बेटे मनोज शर्मा ने मां शीतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल माधव डिस्पेंसरी के सामने भर्ती कराया और उनका इलाज चल रहा है।

ट्रोला ने मारी स्कूटी में टक्कर एक महिला की हुई घटना स्थल पर ही मौत

मोहन मांझी

गोहद –गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोपहर करीब 1/30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 92 पर ग्वालियर की ओर से आ रही स्कूटी क्रमांक एमपी 07 ऐस ई 2582 पर सवार महिला कैलाशी बाई पत्नी मेवाराम उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी दोनिया पूरा गोरमी हाल ग्वालियर से अपने पति मेवाराम के साथ भिंड की ओर आ रही थी उसी समय छीमका के पास आते समय पीछे से आ रहे ट्रौला क्रमांक एमपी 07 एचबी 3814 ने पीछे से टक्कर मार दी जिसमें महिला कैलाशी बाई की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और वाहनों का जाम लगने लगा जिसकी सूचना पर एसडीएम गोहद शुभम शर्मा पटवारी महेंद्र भदौरिया सचिव रसाल सिंह थाना प्रभारी गोपाल सिकरवार सहायक उपनिरीक्षक दर्शन सिंह यादव सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और वाहनों को निकाल कर तुरंत जाम खुलवाया महिला को गोहद अस्पताल भेजा गया जहां से उसका पोस्टमार्टम कर सब उनके परिजनों को सुपुर्द किया।

पुनीत अनुपम साहित्यिक समूह द्वारा ऑनलाइन साहित्यिक प्रतियोगिता आयोजित

पुनीत अनुपम साहित्यिक समूह द्वारा 10 दिसंबर 2020 को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक ऑनलाइन साहित्यिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका विषय मानव अधिकार रखा गया। इस प्रतियोगिता में देशभर के रचनाकारों ने भाग लिया और अपनी रचनाओं के माध्यम से वर्तमान समय में मानव अधिकारों की बढ़ रही आवश्यकताओं का अनुभव करवाया तथा जन साधारण को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया। समूह के निर्णायकों द्वारा रचनाओं की उत्कृष्टता और

रचनाकारों द्वारा रचनाओं में मानवाधिकारों के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर चार सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों अनुसूया बडोनी अंशीकमल (पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड), एस पी दीक्षित (उन्नाव, उत्तर प्रदेश), पुष्पा कुमारी पुष्प (पुणे, महाराष्ट्र), संजू वर्मा (पूर्वी सिंहभूम, झारखंड) को पुनीत मानवता रत्न सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रतियोगिता में नियमानुसार भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पुनीत सहभागिता प्रशस्ति पत्र प्रदान करके साहित्य सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष पुनीत कुमार जी ने? सभी प्रतिभागी रचनाकारों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी और कहा कि पुनीत अनुपम साहित्यिक समूह इसी तरह आगे भी ऑनलाइन साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से साहित्य को मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ता रहेगा तथा समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करता रहेगा। साथ ही उन्होंने समय-समय पर समूह का मार्ग दर्शन करने वाले वरिष्ठ रचनाकारों, समाजसेवी मित्रों और समूह के कार्यक्रमों का समाचार प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकों का आभार भी व्यक्त किया।

अनियंत्रित होकर कार पलटी, कोई जनहानि नही

पिछोर। गुरुवार की शाम एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई हालांकि कार के पलटने से कोई जनहानि नही हुई। बताया जा रहा है गुरुवार की शाम करीब 5 बजे एक कार रन्नौद की ओर से पिछोर जा रही थी रास्ते में मायापुर और पिछोर के बीच हरपालपुरा गांव में अनियंत्रित होकर खाई में जाकर पलट गई हालांकि कोई जनहानि नही हुई लेकिन कार में सवार व्यक्ति घटना के बाद कार को छोड़कर भाग गए।

मानव सामाजिक सेवा एसोसिएशन ने अंकित कुमार को जिला प्रभारी के पद पर नियुक्त किया

मानव सामाजिक सेवा एसोसिएशन के अध्यक्ष/संस्थापक रंजीत सिंह ने अंकित कुमार को औरैया जिला प्रभारी पद पर नियुक्त किया है। और सदस्यता नियुक्ति पत्र देकर जिम्मेदारी सौंपी गई है निशवारथ भाव से कार्य करने की शपथ दिलाई। मानव सामाजिक सेवा एसोसिएशन पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब, कमजोर, असहाय, विकलांग बच्चों की हर सम्भव मदद करेगी, शिक्षा कृषि क्षेत्र में लोगों को जागरूक करेगी , यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य , पर्यावरण, नशामुक्ति के जागरूकता अभियान, राज्य सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता, गरीब महिलाओं को वयूटी पार्लर , सिलाई कढ़ाई का निशुल्क परीक्षण , गरीबों को निशुल्क कानूनी सलाह व मदद देने का काम करेगी अन्य कार्यक्रमों को चलाकर आमजनता को जागरूक करेगी।

सहायकयंत्री एवं उपयंत्री के उपस्थिति में डाला टंकी का ले आऊट

पिछोर। गुरुवार को खनियाधाना के ग्राम नगरेला में नल जल योजना के अंतर्गत पानी की टंकी का ले आउट गौशाला के पास उपयंत्री एच आर पिंबैया एवं सहायक यंत्री अशोक चतुर्वेदी की उपस्थिति में ले आऊट दिया गया। जिसमें पीएचई ब्लॉक कॉर्डिनेटर अमीता गोस्वामी,ग्राम के सरपंच राजूराजा चौहान सहित ग्रामवासी मौजूद रहे।जिसमे सरपंच राजूराजा द्वारा बताया गया कि पानी के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत था अब मेरा वो सपना साकार होने जा रहा है। वहीं सरपंच ने ले आउट देने पर अधिकारियो का आभार व्यक्त किया साथ ही ग्रामवासियों से सहयोग की अपील की गई।

विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर

दतिया। माननीय मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार एवं प्रशासन द्वारा कोविड-19 संबंधी जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती सुनीता यादव के निर्देशन एवं सचिव/ एडीजे श्री दिनेशकुमार खटीक के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर रासजेबी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों ने माता सरस्वती की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजित जागरूकता शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अंकिता शांडिल्य उपस्थित रहीं व कार्यक्रम की अध्यक्षता रासजेबी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर राजेश मोर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पैरालीगल वॉलेंटियर, समाजसेवी रामजीशरण राय उपस्थित रहे।

आयोजित कार्यक्रम में मानव अधिकार के संबंध में मुख्य अतिथि सुश्री अंकिता शांडिल्य द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में व्यापक जानकारी देते हुए मानवाधिकार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता समानता एवं गरमा का अधिकार जो संविधान द्वारा सुनिश्चित अथवा अंतर्राष्ट्रीय भाषा में सन्निहित है तथा भारतीय न्याय मूल द्वारा लागू है बताया उन्होंने मानवाधिकारों में अधिकार एवं दायित्व शामिल है राज्य मानव अधिकारों के गरिमा संरक्षण पर निबंध निर्वहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अधिकार एवं दायित्व दोनों की कल्पना करता है। व्यक्तिगत स्तर पर जिस प्रकार हम अपने और मानवाधिकारों के हकदार हैं वही दूसरों के मानवाधिकारों का भी सम्मान हमें करना चाहिए। अध्यक्षता कर रहे राजेश मोर द्वारा संस्थान के बारे में बताया कि कोई भी नागरिक अपने व्यवसाय में रहते हुए भी मानव अधिकार संरक्षक बन सकता है मानवाधिकार संरक्षक पेशेवर मानवाधिकार करता मानवाधिकार मामलों पर कुछ काम कर रहे वकील पत्रकार व्यापारिक संघ के लोग या विकास कार्यकर्ता हो सकते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रामजीशरण राय द्वारा बताया गया कि हमें अपने क्षेत्र में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए वंचित बनेरी लोगों की आवाज बनने की आवश्यकता है जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते उन्हें हम हैं। उनकी आवाज हम सबको मिलकर उठाना चाहिए और उन्हें प्रदत्त मानवाधिकार दिलाने में सहयोग करना चाहिए। इसी क्रम में पीएलबी शैलेंद्र सविता द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में व्यापक जानकारी देते हुए पैरालीगल वालंटियर के कार्य एवं दायित्व के बारे में बताया साथी पैरालीगल कौन बन सकते हैं बताया राष्ट्रीय संस्थान के प्रभारी प्राचार्य अतुल जैन द्वारा सभी का अतिथियों का स्वागत करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण का धन्यवाद ज्ञापित किया जो खास दिन पर खास विषय को लेकर आयोजन किया गया उपस्थित छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए प्रश्नों का अतिथि पैनल द्वारा सहज व सरल ढंग से समाधान किया गया साथी उनको प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने ज्ञान को और ज्यादा प्रमाणित करने के लिए अधिक से अधिक प्रश्न करने की इच्छा को प्रबल करें। कार्यक्रम में कु. अंकिता शांडिल्य जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि आज हम सभी विश्व मानव अधिकार दिवस की 70 वी सालगिरह मना रहे है। हर साल दिसंबर महीने की 10 तारीख को दुनियाभर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य दुनियाभर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। 1948 में यूएन ने मानव अधिकारों की सर्वभौमिक घोषणा की।किसी भी व्यक्ति का जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने इन अधिकारों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। उन्हें इन अधिकारों से रूबरू कराने के लिए ही मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। मानव अधिकार व्यक्ति कोव जन्म से लेकर मृत्यु तक के साथ चलते है मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी व्यक्ति हकदार है। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जैसे कि जीवन और आजाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। इस अवसर पर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अतुल जैन, भानवेंद्र चतुर्वेदी, किशन गुप्ता, निखिल पमवानी आदि छात्र एवं छात्राएं आदि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी पीएलव्ही शैलेन्द्र सविता ने दी।

प्रदेश के स्कूलों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा: मंत्री श्री परमार

श्री परमार ने सीबीएसई से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों से चर्चा की

भिण्ड। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों को मान्यता के लिये आवेदन के समय मान्यता शुल्क जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। वे आगामी सत्र 2020-21 के अंत तक उक्त शुल्क जमा कर सकेंगे। मंत्री श्री परमार गत दिवस सीबीएससी से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में मुलाक़ात के दौरान चर्चा कर रहे थे। श्री परमार ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना समाज के उत्थान का एक महान सेवार्थ कार्य है। इस कोरोना संकटकाल में हम सभी को साथ मिलकर प्रदेश के बच्चो का भविष्य संवारना है। उन्हें शिक्षा देने के साथ-साथ कोरोना से बचाना भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी हैं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। सीबीएससी से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने आज मंत्री श्री परमार से भेंट की। चर्चा के दौरान अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने मंत्री श्री परमार से कोविड 19 वायरस के संक्रमण के चलते उत्पन्न परिस्थितियों में विद्यालयों के संचालन में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कक्षा एक से बारहवीं तक के बच्चों की ट्यूशन फीस पालकों द्वारा जमा नहीं कराई जा रही है जिससे शिक्षकों के वेतन और स्कूल के संचालन में समस्या आ रही है। इसके साथ ही प्रतिनिधियों ने इस वर्ष का शैक्षणिक सत्र 15 मई 2021 तक बढ़ाने, कक्षा छठवीं और आठवीं को जनवरी 2021 तथा कक्षा पहली से पांचवी तक की कक्षाएं 15 जनवरी 2021 से संचालित करने का सुझाव दिया । उन्होंने मंत्री श्री परमार से आग्रह किया कि अप्रैल 2020 से अनलॉक पीरियड तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल बस टैक्स, आरटीओ परमिट और प्रॉपर्टी टैक्स को माफ कर दिया जाए। मंत्री श्री परमार ने स्पष्ट किया कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन के बारे में शीघ्र ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कक्षा छठवीं से आठवीं तक की कक्षाओं के बारे में निर्णय कोरोना वायरस संक्रमण की परिस्थितियों अनुरूप लिया जाएगा।

नागरिकों को फोटोयुक्त मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाये

भिण्ड। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री धरणेन्द्र कुमार जैन ने स्वीप पार्टनर की बैठक में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाये। श्री जैन ने बताया कि युवा नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 2021 को या उसके पूर्व 18 वर्ष हो चुकी है किन्तु मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है, उनके लिए निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषदों के वार्डों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग नागरिकों को नाम जुड़वाने प्रेरित करें। कॉलेज छात्रों को उच्च शिक्षा विभाग एन.एस.एस. के माध्यम से तथा सामाजिक न्याय विभाग दिव्यांगजनों के नाम जुड़वाने के लिए प्रयास करे। आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं भारत संचार निगम लिमिटेड भी इससे संबंधी जागरूकता अभियान चलाये जिससे अधिक से अधिक संख्या में नागरिक मतदाता सूची में पंजीकृत हो सकें।

श्री जॉन किंग्सले, सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, म. प्र. शासन एवं प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी, भोपाल के सानिध्य में औद्योगिक विकास एवं समस्याओं पर चर्चा का आयोजन आज 'चेम्बर भवन' में

ग्वालियर। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, म. प्र. शासन के सचिव एवं प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी, भोपाल-श्री जॉन किंग्सले के सानिध्य में ग्वालियर अंचल के औद्योगिक विकास एवं समस्याओं पर चर्चा का आयोजन शुक्रवार, 11 दिसम्बर,20 को सायं 04.45 बजे 'चेम्बर भवन' में किया गया है । एमपीसीसीआई, अध्यक्ष-विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष-पारस जैन, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि उद्योग सचिव-श्री जॉन किंग्सले के सानिध्य में आयोजित उक्त बैठक में ग्वालियर अंचल के उद्योगपतियों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जाएगा तथा अंचल में समग्र औद्योगिक विकास पर कुछ सुझाव भी इस अवसर पर उद्योग सचिव व एम.डी.,एमपीआईडीसी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँगे । पदाधिकारियों ने अंचल के उद्यमियों सहित संस्था के सभी सदस्यों से औद्योगिक विकास एवं समस्याओं पर आयोजित आज की चर्चा में अधिक से अधिक संख्या में पधारने की विनम्र अपील की है ।

VISION 2030
ग्वालियर शहर में पहली बार हर सेवा और वस्तु बहुत ही सस्ती
जियो रीचार्ज एक माह 199 वाला केवल 180 में।
आइडिया और एयरटेल का रीचार्ज केवल 225/- में 249 वाला।
किराना का सामान सबसे सस्ता।
HOME TUITION का डेमो फ्री वो भी 15 दिन।
केक केवल 180/- में फ्री HOME DELIVERY के साथ।
टिफिन सेंटर खाना बिल्कुल घर जैसा।
ऐसे ही 5 लाख प्रोडक्ट्स और 50 से ज्यादा सेवाएँ
बस एक कॉल या वॉट्सएप्प, हर सेवा आपके पास।
Only WHATSAPP 9425823988
call-9691937250/- 9516003221

जिला चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें देने हेतु समाज के विभिन्न वर्गो का भी सहयोग लें

ग्वालियर संभागायुक्त श्री सक्सैना ने स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग की बैठक में दिए निर्देश

ग्वालियर। ग्वालियर संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सैना ने दतिया जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय के माध्यम से मरीजों को और बेहतर सुविधायें मिले इसके लिए विभिन्न समाजसेवी, स्वंयसेवी संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों द्वारा जो स्वेच्छा से सहयोग करना चाहते है और उनकी रूची सेवाभावी है इसके लिए प्रति सप्ताह मरीजों की मदद करने हेतु उन से चर्चा करें। संभागायुक्त श्री आशीष सक्सैना ने गुरूवार को उक्त आश्य के विचार न्यू कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक में व्यक्त किए। बैठक में कलेक्टर श्री संजय कुमार, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. एके दीक्षित, महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती सीमा शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वासथ्य अधिकारी डॉ. एसएन उदयपुरिया, जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. एसएन शाक्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह अम्ब सहित अधिकारीगण उपस्थित थे। एसएमएस के माध्यम से महिलाओं को मिलेगी सूचना

संभागायुक्त श्री सक्सैना ने बैठक में स्वास्थ्य एवं महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि स्वास्थ्य और महिला बाल विकास की संयुक्त जिम्मेदारी है कि गर्भवती महिलाओं का एएनसी के दौरान सभी जांच एवं टीकाकरण समय पर हो। इसके लिए प्रत्येक महिला के स्वास्थ्य कार्ड का संधारण भी हो। एएनएम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जांच एवं टीकाकरण की भी जानकारी दी जाए। साथ ही एक सॉफ्टवेयर भी विकसित करें कि एसएमएस के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के मोबाईल या उनके परिवार के किसी सदस्य के मोबाईल पर उनकी जांच एवं टीकाकरण की सूचना मिल सके। जिससे निर्धारित तिथि पर जांच करा सकें। इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाये। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाना है। इसके लिए उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक उपस्थित होकर मरीजों का उपचार करें।

निजी नर्सिंगहोमों का आयुष्मान में पंजीयन कराये–संभागायुक्त श्री सक्सैना ने जिले में स्थित नर्सिंग होम एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से मरीजों को स्वास्थ्य सेवायें मिले इसके लिए पात्रता रखने वाले नर्सिंगहोमों को आयुष्मान योजना के तहत् पंजीयन कराये। जिससे मरीजों को लाभ मिल सके।

एक जनवरी से निजी भवनों में नहीं लगेंगे आंगनबाड़ी केन्द्र–ग्वालियर संभागायुक्त श्री आशीष सक्सैना ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की बैठक में समीक्षा करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक जनवरी 2021 से कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र निजी भवन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के निवास पर संचालित नहीं होगी। निजी भवनों में किराये पर केन्द्र चलते पाए जाने पर कार्यवाही की जायेगी। बैठक में कलेक्टर श्री संजय कुमार ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि मरीजों को और बेहतर सुविधायें मिले इसके लिए विभिन्न समाजसेवी, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारी आदि संगठनों के साथ चर्चा कर कार्यवाही की जायेगी।

आपराधिक विधियों में संशोधन के लिये समिति गठित

ग्वालियर। राज्य शासन द्वारा भारत सरकार (गृह मंत्रालय) के निर्देशानुसार आपराधिक विधियों में सम्यक संशोधन के लिये अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह अध्यक्ष होंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विकास, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर, प्रमुख सचिव विधि और संचालक लोक अभियोजन समिति में सदस्य होंगे। सचिव गृह विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे। विधि एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं कमजोर वर्गों के लिये त्वरित न्याय सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों का जीवन सुगम बनाने के लिये वर्तमान आपराधिक विधियों जैसे भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, शस्त्र अधिनियम तथा नारकोटिक्स एक्ट पर विचार-विमर्श कर उसमें सम्यक संशोधन किया जाना है। पुलिस एवं लोक व्यवस्था संविधान की अनुसूची-7 में राज्य संबंधी विषय है। अतः केन्द्र शासन ने राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित किये हैं। सुझाव देते समय यह ध्यान देना उचित होगा कि पुनरीक्षित कानून जनता की लोकतांत्रिक अपेक्षाओं के अनुरूप हो और महिलाओं तथा बच्चों एवं समाज के कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने में सक्षम हो एवं आम नागरिकों का जीवन सुगम हो सके। समिति अपनी अनुशंसा तीन माह में प्रस्तुत करेगी।

एक वर्षीय अरबी, फारसी और उर्दू कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ

ग्वालियर। मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद की निगरानी में चल रहे कौमी कौंसिल बराए फरोगे उर्दू जबान, भारत सरकार के एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम अरबी भाषा, एक वर्षीय प्रमाण-पत्र फारसी (परशियन) कोर्स और एक वर्षीय उर्दू डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्रारंभ हो गये हैं। अरबी, फारसी और उर्दू भाषा सीखने के इच्छुक इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2021 नियत की गई है। अरबी कोर्स में प्रवेश के लिये उर्दू की प्रारंभिक शिक्षा के अतिरिक्त उर्दू लिखने और समझने का ज्ञान भी आवश्यक है। फारसी कोर्स में प्रवेश के लिये उर्दू एवं अंग्रेजी लिखने और पढ़ने का ज्ञान आवश्यक है। उर्दू डिप्लोमा कोर्स में शैक्षणिक योग्यता की कोई शर्त नहीं है। तीनों पाठ्यक्रमों में आयु सीमा की बाध्यता नहीं है। प्रति कोर्स 200 रुपये पंजीयन शुल्क प्रवेश के समय जमा होंगे। इसके अलावा अन्य कोई फीस नहीं ली जायेगी। कोर्स की किताबें निःशुल्क मिलेंगी। प्रवेश-पत्र सीमित हैं। प्रवेश-पत्र की छाया-प्रति स्वीकार नहीं की जायेगी। फार्म मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी के कार्यालय, मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं। अन्य जानकारी के लिये अकादमी के दूरभाष क्रमांक 0755-2551691 पर कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुसूचित-जनजाति के 96 अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा की दी गई कोचिंग

53 प्रतिभावान प्रतियोगियों को दी गई प्रोत्साहन राशि

ग्वालियर। प्रदेश में जनजातीय वर्ग के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में बेहतर कोचिंग दिलाने के लिये आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग द्वारा पिछले वर्ष 96 अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग दिलवाई गई। विभाग द्वारा इस योजना में 2 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। विभाग द्वारा इसके साथ ही सिविल सेवा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले वर्ष 53 प्रतिभावान प्रतियोगियों को करीब 11 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 40 हजार, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60 हजार तथा साक्षात्कार उत्तीर्ण करने पर 50 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध कराई जाती है।

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार मेलों का आयोजन

ग्वालियर। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार मेलों का आयोजन 14 दिसम्बर से 21 दिसम्बर तक किया जा रहा है। रोजगार मेले में एसईएल मेन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जिला सीहोर, शिव शक्ति बायो टेक्नोलॉजी भोपाल, सिक्यूरिटी एण्ड इंटेलीजेंस सर्विसेज एवं यशस्वी ग्रुप अकादमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट प्रा. लि. द्वारा 350 पदों पर भर्ती की जायेगी। जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार मेला 14 दिसम्बर को जनपद पंचायत चीनौर, 15 दिसम्बर को जनपद पंचायत भवन डबरा, 16 दिसम्बर को ग्राम पंचायत भवन घाटीगाँव, 17 दिसम्बर को सामुदायिक भवन पिछोर, 18 दिसम्बर को जनपद पंचायत भितरवार, 19 दिसम्बर को ग्राम पंचायत भवन सिरसौद, 20 दिसम्बर को ग्राम पंचायत जिगसौली तथा 21 दिसम्बर को ग्राम पंचायत भवन उटीला में आयोजित किया जायेगा। कंपनी में भर्ती हेतु जाने के इच्छुक युवक अपने समस्त दस्तावेज लेकर रोजगार मेले में उपस्थित हों। रोजगार मेले के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु मोबाइल नम्बर 9301756519 एवं 8964986222 पर संपर्क किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रोजगार मेले में कोविड-19 संक्रमण के लिये जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। सभी युवक रोजगार मेले में मुँह पर मास्क लगाकर अवश्य आएँ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

लघु उद्योग निगम का सभी कार्य आन-लाइन हुआ

ग्वालियर। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की 2 नई बेवसाइट से अब निगम के सभी कामकाज ऑनलाइन हो गए है। पिछले सप्ताह ही विभाग के मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने वेबसाईट प्रोक्योरमेंट पोर्टल का लोकार्पण किया था। निगम के प्रबंध संचालक श्री भास्कर लक्षकार ने बताया कि लघु उद्योग निगम द्वारा विकसित कराये गये पोर्टल में प्रोक्योरमेंट के संबंध में शुरू से अंत तक का समाधान उपलब्ध है। पोर्टल पर उपलब्ध डेश बोर्ड के माध्यम से प्रदायकर्ता एवं निगम द्वारा अपनी गतिविधियों का संपादन, पर्यवेक्षण आदि किया जा सकता है। निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु एनआईसी के पोर्टल उच का उपयोग किया जा रहा है एवं समस्त निविदायें इसी पोर्टल पर आमंत्रित की जा रही हैं। पोर्टल पर उपलब्ध दर अनुबंध के आधार पर क्रयकर्ता विभाग व प्रदायकर्ताओं का चयन कर उन्हें प्रदाय आदेश जारी कर सकेंगे। जारी आदेश को संशोधित करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। पोर्टल पर विभाग उनके द्वारा जारी प्रदाय आदेश के संबंध में की गई कार्यवाही का अवलोकन भी कर सकता है। पोर्टल पर ही प्रदायकर्ता द्वारा निरीक्षणकर्ता एजेंसी को निरीक्षण हेतु ऑफर दिये जाने तथा निरीक्षणकर्ता एजेंसी द्वारा निरीक्षण उपरांत पोर्टल पर निरीक्षण के संबंध में संपन्न कार्यवाही का वीडियो एवं निरीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सकता है। प्रबंध संचालक ने बताया कि सामग्री की प्राप्ति के उपरांत प्रदायकर्ता एवं क्रयकर्ता विभाग द्वारा सामग्री प्राप्ति रसीद भी पोर्टल पर अपलोड की जा सकती हैं। निगम द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने से लेकर सामग्री की प्राप्ति तक समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन की जाकर मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने का प्रयास किया गया है। इस तरह निगम प्रोक्योरमेंट से संबंधित संपूर्ण गतिविधि हेतु ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि निगम अपनी गतिविधियों के डिजिटाईजेशन हेतु कृतसंकल्पित एवं इस दिशा में निगम द्वारा ई-ऑफिस प्रणाली को लागू किया जाकर नस्तियों का निराकरण ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जा रहा है।

रूर्बन मिशन के सभी काम जन उपयोगी हों और लोगों की आय भी बढ़े: शेजवलकर

गाँवों का स्वरूप बरकरार रखकर ग्रामीणों को शहर के समान सुविधायें दिलाने के लिये हो रहे हैं काम, सांसद ने की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के कामों की समीक्षा

ग्वालियर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत बनाई जा रहीं अधोसंरचनायें जन उपयोगी हों, साथ ही ऐसे काम हाथ में लिए जाएँ जिनसे ग्रामीणों की आय भी बढ़े। यह बात क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की जिला स्तरीय समिति की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत ऐसे काम जरूर हाथ में लिए जाएँ जो अन्य योजनाओं के तहत नहीं कराए जा सकते। श्री शेजवलकर ने मिशन के तहत निर्माणाधीन नल-जल योजनाओं में पानी के रीचार्ज की संरचनायें जोड़ने पर भी विशेष बल दिया। गुरूवार को जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुई बैठक में जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति के उपाध्यक्ष श्री शांति शरण गौतम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. विजय दुबे सहित संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच व सचिव तथा निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकारी मौजूद थे।

ज्ञात हो भारत सरकार के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत क्लस्टर (गाँवों के समूह) में ग्रामीण अंचल का स्वरूप बरकरार रखते हुए शहर के समान बुनियादी सुविधायें मुहैया कराने के लिये विकास कार्य कराए जाते हैं। साथ ही ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान से संबंधित काम भी कराए जाते हैं। इस मिशन के तहत ग्वालियर जिले की डबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत छीमक क्लस्टर के 14 ग्राम पंचायतों के 28 गाँवों में लगभग 35 करोड़ रूपए की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सांसद श्री शेजवलकर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जिले में रूर्बन मिशन के तहत दो नए क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव तैयार करें। इन क्लस्टर को भारत सरकार से मंजूरी दिलाने के प्रयास किए जायेंगे। श्री शेजवलकर ने बैठक में छीमक क्लस्टर की सभी 14 ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों की ग्राम पंचायतवार समीक्षा की। साथ ही निर्देश दिए कि जो काम पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण कराएँ, ताकि उनका लाभ ग्रामीण जनों को मिल सके। उन्होंने नल-जल योजनाओं के काम फरवरी माह तक तथा शेष अन्य काम आगामी 31 मार्च तक पूर्ण कराने पर जोर दिया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा ने बैठक में रूर्बन मिशन के तहत छीमक क्लसटर में चल रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएँ। उन्होंने कहा जल कर सहित अन्य करों को जमा करने के लिये लोगों को प्रेरित करें। रूर्बन मिशन के तहत छीमक क्लस्टर में 7 सामुदायिक भवन, गोदाम सहित 8 उचित मूल्य की दुकानों के भवन, 12 गाँवों के हर घर तक नल से पानी पहुँचाने के लिये पानी की बड़ी टंकी सहित नल-जल योजनायें, स्कूलों की बाउण्ड्रीवॉल, बास्केटबॉल व बैडमिंटन के खेल मैदान तथा वर्षा जल प्रबंधन के लिये चैकडैम सहित अन्य निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही क्षेत्रीय किसानों को उन्नत कृषि के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से एग्रो पार्क व कृषि ज्ञान केन्द्र सह बीज भण्डार, अजोला पिट, वर्मी कम्पोस्ट, पॉली हाउस, कस्टम हायरिंग सेंटर, कैटल फीड यूनिट, हैचरी यूनिट सहित खेती से संबंधित अन्य कार्य कराने की एक वृहद योजना को भी मूर्तरूप दिया जायेगा। इसके अलावा डेयरी उत्पाद एवं दुग्ध शीत केन्द्र का निर्माण भी छीमक क्लस्टर में शामिल किया गया है। सांसद श्री शेजवलकर ने कहा कि एग्रो पार्क की स्थापना विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में की जाए, जिससे क्षेत्रीय किसान आधुनिक खेती से जुड़कर अपनी आय में इजाफा कर सकें। इसी तरह क्लस्टर के सभी गाँवों में दुग्ध संग्रहण की क्षमता व मिल्क रूट का व्यवहारिक अध्ययन करने के बाद ही दुग्ध शीत केन्द्र की स्थापना की जाए।

दीदी कैफे पर चाय पी एवं पैसे भी चुकाए–श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की समीक्षा करने आए सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने बैठक के बाद जिला पंचायत परिसर में स्थित दीदी कैफे में बैठकर चाय पी एवं अपनी जेब से पैसे निकालकर भुगतान भी किया। ज्ञात हो कि दीदी कैफे का संचालन ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूह के उन सदस्यों द्वारा किया जा रहा है जो प्रवासी मजदूर थे। लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रांत से लौटकर आए इन श्रमिकों को जब कोई रोजगार नहीं मिला तब जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा की पहल पर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दीदी कैफे के माध्यम से इन श्रमिकों को रोजगार दिलाया गया।

नवगठित नगरीय निकायों में नियुक्त होंगे प्रशासक

ग्वालियर। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नवगठित नगरीय निकायों में समस्त शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये प्रशासक नियुक्त करने के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। प्रशासकों की नियुक्ति आम निर्वाचन सम्पन्न होने और नवीन परिषद् द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक के लिये की गई है। हरदा जिले की नगर परिषद् सिराली, बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, मंदसौर जिले की भैंसोदा, शिवपुरी जिले की रन्नौद, पोहरी, मगरोनी, भिण्ड जिले की रौन, मालनपुर, रीवा जिले की डभौरा, शहडोल जिले की बकहो, अनूपपुर जिले की डोला, डुमरकछार, बनगवां, उमरिया जिले की मानपुर, सागर जिले की बिलेहरा, सुरखी, सिवनी जिले की केवलारी, छपारा, खरगोन जिले की बिस्टान, बड़वानी जिले की ठीकरी, निवाली बुजुर्ग, धार जिले की गंधवानी, ग्वालियर जिले की मोहना, गुना जिले की मधुसूदनगढ़, अशोकनगर जिले की पिपरई और पन्ना जिले की नगर परिषद् गुनौर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करने के लिये जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

साँप काटने से मृत्यु होने पर परिजन को 4 लाख की सहायता

ग्वालियर। साँप काटने के कारण मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिजन को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। कमल सिंह पुत्र विद्याराम निवासी ग्राम सुसेरा की पुत्री प्रियंका उम्र 13 वर्ष को रात्रि में साँप के काटने से जेएएच अस्पताल ग्वालियर में इलाज के लिये लाया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्वालियर श्री प्रदीप तोमर ने बताया कि नायब तहसीलदार वृत्त पुरानी छावनी के प्रतिवेदन के आधार पर मृतक के पिता श्री कमल सिंह पुत्र विद्याराम को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के अनुसार 4 लाख रूपए की सहायता स्वीकृत कर प्रदान की गई है।

सम्पर्क व कॉल का समय 11 से 4 बजे तक
|| श्री गणेशाय: नम: ||
रैरा रजिस्टर्ड फर्म
सौम्या प्रोपर्टी डीलर
आवासीय भूमि (प्लॉट, फ्लैट, मकान, बंगला, खरीदने, बेचने व किराये) पर लेने देने के लिये सम्पर्क करें

9301759475, 9713253992
ऑफिस: शॉप नं. 3-4, तोमर मार्केट, गायत्री मन्दिर वाली गली, पिन्टो पार्क, ग्वा.

PTV NEWS INDIA
प्रतिभा हम निखारेंगे
PUSHPANJALI TODAY न्यूज़ नई सोच नई पहल
अगर आपके अंदर है कोई जज़्बा तो उभर कर आइये आगे आपकी लिखी हुई कहानी, लेख, कविताओं को हम देंगे जगह आपके अंदर की प्रतिभा को हम उभारेंगे।
तो देर किस बात की हमे भेजें अपनी कविता, लेख, कहानियां फिर देश की आर्थिक स्थिति या फिर स्वच्छता के ऊपर अपने विचार
आप हमें व्हाट्सप या मेल भी कर सकते हैं
हमारा उद्देश्य भारत में छिपी प्रतिभाओं को बाहर निकालना।
PUSHPANJALI TODAY न्यूज़ नई सोच नई पहल
Whatsapp :- 9425665944,7999246560, 9691270207
gmail - pushpanjalitoday@gmail.com
नोट - व्हाट्सएप या मेल करते समय ध्यान रखे भेजने वाला व्यक्ति अपनी फोटो ओर नाम/ पता / अवश्य भेंजे

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक, एवं संपादक- भरत सिंह चौहान। पुष्पांजली प्रिंटर्स गोवर्धन कॉलोनी, भिण्ड रोड, गोला का मंदिर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) से मुद्रित एवं दीपू इलेक्ट्रोनिक्स, पंजीयन क्रमांक/ एम.पी.एच.आई.एन. /31130 निकट हनुमान मंदिर, गोवर्धन कॉलोनी, भिण्ड रोड, गोला का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक - भरत सिंह चौहान E-mail : pushpanjalitoday17@gmail.com 0751-4901333, M.: 8269307478